www.adbhutsamachar.com

अद्भुत समाचार

वर्ष – 15 | अंक–35 | RNI-No. : UPHIN/2011/43806 | लखनऊ, शनिवार 03 जनवरी, 2026 | प्रातः कालीन संस्करण | (हिन्दी दैनिक) | पृष्ठ–4 | मूल्य 1 रुपया

इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, उमा भारती ने व्यवस्था पर उठाये सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी के कारण कई लोगों की मौत को लेकर शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश कुप्रशासन का केंद्र बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गरीबों की मौत पर हमेशा की तरह खामोश हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि जीवन के अधिकार की ''हत्या'' के लिए भाजपा का ''डबल इंजन'' जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''इंदौर में पानी नहीं, जहर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर–घर मातम है, गरीब बेबस हैं और ऊपर से भाजपा नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थीय सरकार ने घमंड परोस दिया।'' उन्होंने सवाल किया कि लोगों ने बार–बार गंदे, बदबूदार पानी की शिकायत की तो फिर सुनवाई क्यों नहीं हुई? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ''सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते आपूर्ति बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी?'' उन्होंने कहा, ''ये 'फोकट' सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है। और इस अधिकार की हत्या के लिए भाजपा का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है।'' राहुल गांधी ने आरोप लगाया, ''मध्यप्रदेश अब कुप्रशासन का केंद्र बन चुका है – कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे, और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। और जब–जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं।''इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से फैले उल्टी–दस्त के प्रकोप से 10 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। बहरहाल, स्थानीय नागरिकों ने इस प्रकोप से छह माह के बच्चे समेत 14 लोगों के दम तोड़ने का दावा किया है। इस दावे की स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि नहीं की है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों को लेकर मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सरकार और व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को प्रदेश, सरकार और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए शर्मनाक और कलंकित बताया है। उमा भारती ने सवाल उठाया कि दूषित पानी के इस गंभीर मामले में आखिर यह कौन कह रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती या हमारी चली नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ थे, तो पद पर बैठे रहते हुए बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे और जनता के बीच जाकर उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझी। पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि वर्ष 2025 के अंत में इंदौर में गंदा पानी पीने से हुई मौतों ने पूरे प्रदेश और शासन–प्रशासन को शर्मिंदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस शहर को प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला, वहां इतना गंदा और जहरीला पानी लोगों की जान ले रहा है और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उमा भारती ने मुआवजे की राशि पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिंदगी की कीमत दो लाख रुपये नहीं होती, क्योंकि मृतकों के परिजन जीवन भर इस दुख के साथ जीते हैं। उन्होंने इसे पाप करार देते हुए कहा कि ऐसे मामलों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, केवल घोर प्रायश्चित, पीड़ितों से माफी और दोषियों को अधिकतम दंड ही इसका समाधान है। उन्होंने यह भी कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी इस अपराध के जिम्मेदार हैं, उन सभी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।

Defence Sector में आत्मनिर्भरता पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान

15-20 साल में बनेंगे ग्लोबल लीडर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि भारत अगले 15-20 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा, जिसमें देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की प्रगति और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य पर भी जोर दिया।

नई दिल्ली (एजेंसी)रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि अगले 15–20 वर्षों में भारत हथियारों के मामले में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स की बढ़ती प्रवृत्ति की सराहना की। उदयपुर स्थित भूपाल नोबेल विश्वविद्यालय के 104वें स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज रक्षा क्षेत्र में कई स्टार्टअप्स सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हमारे स्टार्टअप्स जो कुछ भी बना रहे हैं, वह जमीनी हकीकत के करीब है और वैश्विक मानकों को भी पूरा करता है।राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की प्रगति में सहायक हो सकने वाले नवाचारों के बारे में समाज को जागरूक रहना आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 2014 में 76वें स्थान से 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय आय में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान भी बढ़ा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बदलती प्रौद्योगिकी के सार्वजनिक उपयोग के माध्यम से हम भारत की प्रगति को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमें तेजी से विकसित हो रहे नवाचारों के बारे में निरंतर जानकारी रखनी चाहिए। आज कमी ज्ञान, डेटा या सूचना की नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता की है। आतंकवादी निरक्षर नहीं होतेय उनके पास भी उच्च डिग्रियां होती हैं, लेकिन उनमें बुद्धिमत्ता की कमी होती है। जब विवेक के बिना ज्ञान होता है, तो व्यक्ति ऐसे तरीकों से काम करता है जो समाज के लिए विभाजनकारी होते हैं।अपने भाषण का समापन करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, ''आज जब भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। 2047 तक, हमें एक विकसित भारत का निर्माण करना होगा जो समृद्ध और बुद्धिमान दोनों हो।'' राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि आधुनिक भारत अपने प्राचीन अतीत और सांस्कृतिक परंपराओं को मान्यता देकर शक्ति और गौरव प्राप्त करता है। उदयपुर स्थित भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के 104वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए, जिसका नाम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1923 में इसकी स्थापना की थी, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने विज्ञान, चिकित्सा, गणित, व्याकरण, दर्शन और नैतिकता जैसे विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रणालियों में भारत के स्थायी योगदान पर प्रकाश डाला।सिंह ने कहा कि आज का भारत अपने अतीत पर गर्व करता है। आज का भारत अपनी परंपराओं का सम्मान करता है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को गौरवान्वित करता है। भारत की धरती ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट, ब्रह्मगुप्त, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, पिंगला, मैत्रेयी, गार्गी और तिरुवल्लुवर जैसे विद्वानों को जन्म दिया है।

हिमाचल प्रदेशः प्रोफेसर ने किया यौन उत्पीड़न तो छात्राओं ने की मारपीट, इलाज के दौरान पीड़िता की मौत, मामला दर्ज

शिमला 02 जनवरी (एजेंसी)हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित एक सरकारी कॉलेज की तीन छात्राओं के खिलाफ रैगिंग और मारपीट के आरोप में, जबकि एक प्रोफेसर के खिलाफ 19 वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पीड़ित छात्रा की पिछले साल 26 दिसंबर को लुधियाना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद बृहस्पतिवार को यह मामला दर्ज किया गया। उसने बताया कि यह कार्रवाई पीड़िता के पिता की शिकायत पर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 18 सितंबर, 2025 को तीन वरिष्ठ छात्राओं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की थी। साथ ही, उन्होंने कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार पर छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने और यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने बताया कि पिता के अनुसार, इसी पिटाई और प्रताड़ना के कारण उनकी बेटी की हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिता ने कहा कि उनकी बेटी गहरे सदमे में थी, जिसके कारण पहले शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75, 115(2) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

यही डिवाइस पुलिसवाले के सिर पर... नागरिकता परीक्षण वाले वीडियो पर भड़के ओवैसी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गाजियाबाद के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को एक व्यक्तिकी पीठ पर स्मार्टफोन जैसा कुछ रखते हुए और यह कहते हुए दिखाया गया कि वह बांग्लादेश से है। पुलिस ने बाद में कहा कि यह घटना एक झुग्गी बस्ती में नियमित क्षेत्र नियंत्रण अभ्यास के दौरान हुई।

एजेंसी/नई दिल्ली (एजेंसीएआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को गाजियाबाद पुलिस की उस वायरल वीडियो को लेकर आलोचना की, जिसमें एक अधिकारी को एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता की श्जांचश् करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करते हुए दिखाया गया है, और इसे घृणा और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह का स्पष्ट उदाहरण बताया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गाजियाबाद के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को एक व्यक्ति की पीठ पर स्मार्टफोन जैसा कुछ रखते हुए और यह कहते हुए दिखाया गया कि वह बांग्लादेश से है। पुलिस ने बाद में कहा कि यह घटना एक झुग्गी बस्ती में नियमित क्षेत्र नियंत्रण अभ्यास के दौरान हुई।ओवैसी ने ट्विटर पर श्गाजियाबाद पुलिसकर्मी ने व्यक्ति की राष्ट्रीयता की जांच के लिए उपकरण का इस्तेमाल किया, उसे बताया कि वह श्बांग्लादेश का हैश्य जांच के आदेशश शीर्षक वाली मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा, यही उपकरण पुलिसकर्मी के सिर पर भी लगाया जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि उसके दिमाग में मस्तिष्क है या नहीं। यह नफरत और सांप्रदायिक भेदभाव का स्पष्ट उदाहरण है क्योंकि पीड़ित का नाम मोहम्मद सादिक है, जो बिहार के अररिया का रहने वाला है। वीडियो में एक अधिकारी एक महिला और एक पुरुष से कहते हुए सुनाई दे रहा है, ''झूठ मत बोलोय हमारे पास झूठ पकड़ने वाली मशीन है।बातचीत के दौरान, महिला और उसके बगल में खड़ी एक नाबालिग लड़की लगातार इस बात पर जोर देती रहीं कि वे बिहार के अररिया से हैं और उन्होंने मोबाइल फोन पर दस्तावेज भी दिखाए, लेकिन करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मियों का समूह आश्वस्त नहीं हुआ। डीसीपी (ट्रांस–हिंडन) निमिश पाटिल ने बताया कि यह वीडियो 23 दिसंबर को बिहारी मार्केट इलाके की झुग्गी बस्ती में कौशांबी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवानों द्वारा चलाए गए क्षेत्र नियंत्रण अभ्यासष के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

कूटनीतिक प्रयासों की सफलताः 2014 से अब तक पाकिस्तान से 2732 भारतीयों की वतन वापसी

नई दिल्ली। भारत सरकार के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, 2014 से अब तक पाकिस्तान से 2661भारतीय मछुआरों और 71 भारतीय नागरिक कैदियों को वापस लाया गया है। इसमें 500 भारतीय मछुआरे और 13 भारतीय नागरिक कैदी शामिल हैं, जिन्हें 2023 से अब तक पाकिस्तान से सुरक्षित हमवतन वापस लाया गया है। दोनों देशों द्वारा अपनी हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की जारी की गई सूची में यह जानकारी मिली है। 2008 के काउंसलर एक्सेस पर द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2026 को राजनयिक चौनलों के जरिए, नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ, एक–दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की लिस्ट का आदान–प्रदान किया। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 391 नागरिक कैदियों और 33 मछुआरों की जानकारी वाली लिस्ट शेयर की है, जो पाकिस्तानी हैं या जिनके पाकिस्तानी होने का संदेह है। इसी तरह, पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 58 नागरिक कैदियों और 199 मछुआरों की जानकारी वाली लिस्ट शेयर की है, जो भारतीय हैं या जिनके भारतीय होने का संदेह है। मंत्रालय ने कहा भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से नागरिक कैदियों, मछुआरों और उनकी नावों के साथ–साथ लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की जल्द रिहाई और स्वदेश वापसी की मांग की है। पाकिस्तान से उन 167 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी में तेजी लाने का भी आग्रह किया गया है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। इसके अलावा पाकिस्तान से उसकी हिरासत में मौजूद 35 नागरिक कैदियों और मछुआरों को तुरंत काउंसलर एक्सेस देने के लिए कहा गया है, जिनके भारतीय होने का संदेह है और जिन्हें अब तक काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी को नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ डिप्लोमैटिक चौनलों के जरिए, भारत–पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटीज पर हमले पर रोक के एग्रीमेंट के तहत आने वाले न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटीज की लिस्ट भी एक्सचेंज की है।

(रिपोर्ट. शाश्वत तिवारी)

मोदी सरकार में पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना खत्म होने के कगार पर पहुंची : कांग्रेस

नई दिल्ली (एजेंसी कांग्रेस ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शुक्रवार को दावा किया कि नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पैसे का उचित आवंटन नहीं करने के कारण पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। पार्टी के 'पूर्व सैनिक विभाग के प्रमुख कर्नल (सेवानिवृत्त) रोहित चौधरी ने सरकार से आग्रह किया कि इस योजना के लिए हर साल 14 हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाए। चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, ''जवानों को ये भरोसा रहता है कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकार उनका और उनके परिवार का ध्यान रखेगी। लेकिन मोदी सरकार इस भरोसे के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। 2003 में सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) शुरू किया गया था। कहा गया था कि ये एक कैशलेस और कैपलेस योजना होगी। उन्होंने दावा किया कि कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि इतने दिनों में पूर्व सैनिकों की तादाद बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार ने उसके हिसाब से न कोई व्यवस्था बनाई और न ही पैसे का आवंटन बढ़ाया है। चौधरी का कहना है ''कैग की रिपोर्ट बताती है कि सेना में जवानों की कमी है इसलिए जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए। इसके अलावा, ईसीएचएस पूरी तरह से तबाही की कगार पर खड़ी है। साल 2023–24 में 13,500 करोड़ रुपये की जरूरत थी, लेकिन बदले में सिर्फ 9,831 करोड़ रुपये मिले। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक कल्याण विभाग किसी भी हाल में ईसीएचएस चलाने के लिए सक्षम नहीं है तथा ऐसे में इसे इसे सीडीएस के तहत लाया जाए।

मीटिंग के बीच बीजेपी एमएलए को Sudden Heart Attack जन्मदिन के एक दिन बाद निधन,मोदी-योगी ने जताया दुख

उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित फरीदपुर से बीजेपी विधायक ड॰. श्याम बिहारी लाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने अपने 60वें जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद एक बैठक के दौरान तबीयत बिगड़ने पर अंतिम सांस ली, जिससे राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है।

नई दिल्ली (एजेंसी)उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को निधन हो गया। वे बरेली जिले के फरीदपुर निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विधायक को दिल का दौरा पड़ा और पीलीभीत रोड स्थित मेडिसिटी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। गौरतलब है कि उन्होंने ठीक एक दिन पहले 1 जनवरी को अपना 60वां जन्मदिन मनाया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भाजपा विधायक को सर्किट हाउस में दिल का दौरा पड़ा। इससे कुछ समय पहले ही वे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ एक बैठक में शामिल हुए थे। बैठक के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां तमाम कोशिशों के बावजूद उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मोदी ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के फरीदपुर के विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जनहित में समर्पित भाजपा के एक कर्मठ नेता थे, जिनके जाने से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति!उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, ''बरेली जिले के फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल जी के अचानक निधन से मुझे अत्यंत गहरा दुख हुआ है। मेरी ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को इस अपार क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति!''पीलीभीत रोड स्थित शक्ति नगर कॉलोनी के निवासी डॉ. श्याम बिहारी लाल रोहिलखंड विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रमुख भी रह चुके हैं। उन्होंने पहली बार 2012 में भाजपा के टिकट पर फरीदपुर (आरक्षित) विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन मामूली अंतर से हार गए थे। उन्होंने 2017 में फिर से चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉ. सियाराम सागर को हराकर जीत हासिल की। ध्द2022 के विधानसभा चुनावों में श्याम बिहारी लाल ने फरीदपुर निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार जीत दर्ज की, जिससे इस क्षेत्र में एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई।

बजट का समयबद्ध उपयोग सर्वोच्च प्राथमिकता, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्तः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान विभिन्न विभागों को आवंटित बजट के व्यय की प्रगति को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि बजट का समय से और प्रभावी उपयोग प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिक बजट प्राविधान वाले प्रदेश के प्रमुख 20 विभागों की अद्यावधिक स्थिति पर गहन चर्चा की।बैठक में विभागों को शासन स्तर से जारी स्वीकृतियों, विभागाध्यक्षों द्वारा किए गए आवंटन और वास्तविक व्यय की प्रगति का प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवंटित बजट का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाए, जिससे योजनाएं और परियोजनाएं निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण हो सकें और प्रदेशवासियों को उनका लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि बजट खर्च करने के लिए अधिकारियों को निर्णय लेने का सामर्थ्य विकसित करना होगा, क्योंकि निर्णय में देरी योजनाओं की गति को बाधित करती है।मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है, वहां विभागीय मंत्री और अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर प्रत्येक माह समीक्षा बैठक करें और कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि बजट के समय से व्यय के लिए प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए तथा इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए त्वरित और प्रभावी निर्णय लेना आवश्यक है।केंद्र सरकार से संबंधित बजट प्रावधानों को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन विभागों को केंद्र से विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि मिलनी है, उनके संबंधित मंत्री, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्वयं दिल्ली जाकर बजट जारी कराने के लिए सक्रिय प्रयास करें। इसके साथ ही केंद्र सरकार को नियमित रूप से पत्र भेजे जाएं और फोन के माध्यम से निरंतर फॉलोअप किया जाए। इस दिशा में मुख्य सचिव को भी पहल करने के निर्देश दिए गए।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन विभागों के बजट व्यय की प्रगति संतोषजनक नहीं है

2026 भारत की प्रगति का लिखेगा नया अध्याय

भारत 2026 में भी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने की राह पर है। इसके पीछे मजबूत आर्थिक वृद्धि, कम मुद्रास्फीति और बैंकिंग सेक्टर का सुदृढ़ प्रदर्शन जैसे कारक हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 में जिस गति से अर्थव्यवस्था ने बढ़त दिखाई, उसे बनाए रखने के लिए सरकार नई सुधार योजनाओं पर काम कर रही है। केंद्र सरकार आगामी बजट में पूंजीगत व्यय और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठा सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि जीवन सुगमता और कारोबार सुगमता को बढ़ाकर भारत को निवेश के लिए और आकर्षक बनाना। इससे शुल्क और भू–राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। नए साल 2026 की शुरुआत शेयर बाजार के लिए उत्साह भरी रही। साल के पहले ही कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ आगाज किया, जिससे निवेशकों के चेहरे खिल उठे। घरेलू और वैश्विक संकेतों के बीच बाजार में खरीदारी का माहौल देखने को मिला और प्रमुख सूचकांक हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। खास बात यह रही कि ऑटो, मेटल और बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। शेयर बाजार ने किया नए साल का स्वागत! 2026 के पहले दिन सेंसेक्स–निफ्टी में दिखा जोश, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स चमके

नए साल 2026 की शुरुआत शेयर बाजार के लिए उत्साह और उम्मीदों से भरी रही। बाजार खुलते ही बीएसई सेंसेक्स 186 अंकों की तेजी के साथ 85,406 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी करीब 65 अंक चढ़कर 26,194 के आसपास कारोबार करता दिखा। भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ आगाज किया, जिससे निवेशकों के चेहरे खिल उठे। घरेलू और वैश्विक संकेतों के बीच बाजार में खरीदारी का माहौल देखने को मिला और प्रमुख सूचकांक हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। खास बात यह रही कि ऑटो, मेटल और बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसने बाजार को मजबूती दी।

बीएसई सेंसेक्स 1 जनवरी 186. 17 अंकों की बढ़त के साथ 85,406. 77 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी 64.95 अंक चढ़कर 26,194.55 पर पहुंच गया। बाजार की चौड़ाई भी मजबूत रही, जहां कुल 1,284 शेयरों में तेजी दर्ज की गई, जबकि 728 शेयरों में गिरावट रही और 151 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह आंकड़े साफ तौर पर बाजार में सकारात्मक सेंटिमेंट की ओर इशारा करते हैं।सुबह के कारोबार में एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, टाटा स्टील, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा बैंक भी प्रमुख मूवर्स के तौर पर उभरे। मेटल और ऑटो सेक्टर के शेयरों में आई मजबूती ने निवेशकों का ध्यान खींचा, जिससे इन सेक्टर्स में खरीदारी बढ़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2025 में हर मोर्चे पर सफलता हासिल की और सबसे तेज गति से आगे बढ़ती रही। हाल ही में जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अब भारत से आगे सिर्फ जर्मनी, चीन और अमेरिका ही हैं। वहीं,दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाओं ने भारत की जीडीपी की चमकीली तस्वीर दिखाई है। अगर इसी गति से भारत आगे बढ़ता रहा तो अगले ढाई से तीन साल में जर्मनी को पछाड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

आधार वर्ष 2011–12 पर आध ाारित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर लगातार बढ़ी है। 2025–26 की दूसरी तिमाही में यह 8.2 प्रतिशत पर पहुंच गई। खुदरा मुद्रास्फीति साल के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक की निचली सीमा से दो प्रतिशत से भी कम रही। सरकार ने बताया कि भारत ने 4180 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया है। अनुमान है कि 2030 तक 7300 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। बता दें 2025 में आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से मजबूत घरेलू मांग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग, कम मुद्रास्फीति और स्थिर निवेश के कारण हुई। सेवा क्षेत्र का विस्तार लगातार बना रहा, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में भी वापसी हुई। कृषि में बेहतर खरीफ उत्पादन और पर्याप्त खाद्यान्न भंडार ने कीमतों को स्थिर रखने में मदद की। इन सभी कारकों ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा। आप को बता दें कि साल 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8. 2 फीसद रही है। यह दिखाता है कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत ने महंगाई पर काबू पाया। वहीं, बेरोजगारी दर भी कम हुई। जीएसटी में छूट देने से लोगों के पास पैसा आया और भारतीय अर्थव्यवस्था ने नया मुकाम हासिल किया। तमाम रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि 2026 में भी भारत जी–20 देशों में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नवंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 0.71 फीसद पर आ गई। वहीं, नवंबर में बेरोजगारी दर कम होकर 4.7 फीसद रह गई है, जो अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तरहै। देश में ग्रोथ रेट ऊंची है और महंगाई बेहद कम, इसे श्गोल्डिलॉक्सपीरियडश कहा जाता है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था 2025–26 में 6.5 फीसद और 2026–27 में 6.7 फीसद की रफ्तार सेबढ़ेगी। यह वृद्धि घरेलू मांग, कर कटौती और ब्याज दरों में कमी से प्रेरित होगी। मूडीज ने भी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक अनुमान लगाया है। एजेंसी का अनुमान है कि 2026 में 6.5 फीसद की वृद्धि दर रहेगी। यह वृद्धि घरेलू मांग, निर्यात बाजारों में विविधीकरण और अनुकूल मौद्रिक नीति रुख से समर्थित होगी। मूडजी का अनुमान है कि भारत जी–20

अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। फिच ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 7. 4 फीसद ग्रोथ का अनुमान जताया है। एडीबी ने भीभारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपना अनुमान बढ़ाकर 7.2 फीसद कर दिया है,जो मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और बढ़ते निवेश के कारण है।वहीं, विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत की जीडीपी बढ़ोतरी 2026 में 6. 5फीसदी हो सकती है। बता दें कि भारत की जीडीपी का कुल वैल्यूएशन अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर (करीब 350 लाख करोड़) हो गया है। जापान को पीछे छोड़ने के बाद अगले 2.5 से 3 साल में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगाऔर साल 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर (655 लाख करोड़) की इकोनॉमी के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई) ने ग्रोथ ट्रेंड को देखते हुए पूरे साल के लिए इसका अनुमान6.8 फीसद से बढ़ाकर 7.3 फीसद कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक चुनौतियां होने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है।

आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करने को तैयार है। वहीं सरकार का कहना हैकि भारत 2047 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। महंगाई अभी नियंत्रण में है और तय सीमा से नीचे है। बेरोजगारी धीरे–धीरे कम हो रही है और देश के निर्यात में लगातार सुधार हो रहा है। 2026 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर साबित होगा और रूपये का अवमूल्यन खत्म हो कर सकारात्मक रुख की ओर बढेगा। (हिफी)

सम्पादकीय

सार्वजनिक सुनवाई से डरती राजनीतिक पार्टियां

किसी भी लोकतंत्र में, सत्ता में कोई भी पार्टी क्यों न हो, ऐसे अधिकारियों को बुलाने, उन्हे जवाबदेह बनाने के कई लाभ हैं। सबसे पहले, यह जवाबदेही सुनिश्चित करता है। चुने हुए प्रतिनिधि कार्यकारी अधिकारियों से सवाल कर सकते हैं, जो जनता की ओर से होता है। इससे भ्रष्टाचार, दुरुपयोग या नीतिगत असफलताओं पर रोशनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में पटेल की सुनवाई से एपस्टीन फाइलों पर जनता को जानकारी मिली, जो अन्यथा छिपी रह सकती थी।

अमेरिका की व्यवस्था और राजनीति में हाल फिर एक ऐसी घटना घटी जब एफबीआई निदेशक काश पटेल को कांग्रेस की हाउस ज्यूडिशियरी कमिटी ने तलब किया। दिसंबर 2025 में ही उनसे जवाब तलब हुआ। पटेल को जेफरी एपस्टीन फाइलों, एफबीआई की पारदर्शिता और अन्य विवादास्पद मुद्दों पर अमेरिकी सांसदों ने कड़े सवाल किए। सुनवाई के दौरान एक एपस्टीन वीडियो चलाया गया, जिससे सदन में हंगामा हुआ। पटेल ने दावा किया कि एपस्टीन की फाइलों में इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि उन्होंने अन्य लोगों को ट्रैफिकिंग की गई पीड़िता महिलाएं प्रदान की थी। और जांच पुराने गैर–अभियोजन समझौतों से बंधी हुई है।

उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने ही एपस्टीन के खिलाफ मामले को खोला था जबकि पहले के प्रशासन (ओबामा और बाइडेन) ने फाइलें जारी नही कीं। डेमोक्रेट सांसदों ने पटेल पर ट्रंप को बचाने का आरोप लगाया, जबकि पटेल ने इनकार किया। उन्होने कहा कि सभी कानूनी रूप से जारी करने योग्य जानकारी साझा की जा रही है। सुनवाई में एजेंटों की पुनर्नियुक्ति, चार्ली किर्क की हत्या की जांच और एफबीआई के राजनीतिकरण जैसे मुद्दे भी उठे, जहां पटेल ने अपराध दर में कमी और गिरफ्तारियों में वृद्धि का हवाला दिया।

यह सुनवाई अमेरिकी लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता को दर्शाती है। कांग्रेस याकि संसद द्वारा कार्यकारी अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से जवाबदेह ठहराना वहां परंपरा है। काश पटेल, जो ट्रंप के करीबी सहयोगी हैं और एफबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त हुए, को सितंबर 2025 में भी सीनेट और हाउस कमिटियों के समक्ष भी पेश होना पड़ा था। लेकिन दिसंबर की सुनवाई अधिक विवादास्पद रही क्योंकि इसमें एपस्टीन स्कैंडल पर फोकस था। सुनवाई के दौरान सांसदों ने पटेल से सीधे सवाल किए, जैसे एपस्टीन फाइलों में ट्रंप का नाम कितनी बार आया और क्यों रेडैक्शन (संशोध ान) के लिए लगभग 1,000 एजेंटों को लगाया गया।

पटेल ने इनकार किया कि संसाधनों का दुरुपयोग हुआ और कहा कि जांच चल रही है, लेकिन अदालती आदेशों से बंधे हैं। इस तरह की सुनवाई लाइव प्रसारित होती हैं, जो जनता को सीधे देखने का अवसर देती हैं और यह अमेरिकी संविधान की जांच और संतुलन की व्यवस्था का हिस्सा है।

यदि तुलना की जाए तो भारत में भी यों संसद द्वारा किसी अधिकारी को बुलाने की प्रक्रिया है। लेकिन यह अमेरिकी कांग्रेस की तरह सार्वजनिक और जवाबदेही में सख्त नहीं होती। भारतीय संसद की स्थायी समितियां, जैसे लोक लेखा समिति (पीएसी), अनुमान समिति या संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी), अधिकारियों को बुला सकती हैं और पूछताछ कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में जेपीसी ने अधिकारियों को समन किया था, लेकिन ये कार्यवाहियां बंद दरवाजों के पीछे होती हैं, मीडिया को अनुमति नहीं होती और कोई लाइव ब्रॉडकास्ट भी नहीं होता।

अमेरिका में जहां सुनवाई टीवी पर लाइव होती है और सांसद अध िकारियों को कड़े सवाल भी कर सकते हैं, भारत में यह गोपनीय रहती है ताकि जांच प्रभावित न हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 118 के तहत समितियां स्वतंत्र हैं, लेकिन सार्वजनिक सुनवाई की परंपरा नहीं है।

क्या भारत में कभी ऐसी सुनवाई हो सकती है? यह संभव है, लेकिन राजनीतिक घोटालों के बावजूद राष्ट्रपति प्रणाली में व्यवस्था का चौक–बैलेंस है। जबकि यहां प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, इसलिए अध िकारी को बुलाना मंत्री की जिम्मेदारी पर सवाल उठा सकता है, जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। यदि कोई बड़ा घोटाला हो, जैसे राफेल डील या कोयला घोटाला आदि, तो जेपीसी तो अवश्य बन सकती है, लेकिन सार्वजनिक सुनवाई से राजनीतिक पार्टियां डरती हैं क्योंकि इससे संसद में हंगामा, इस्तीफे या सरकार गिरने का खतरा होता है।

हालांकि, डिजिटल युग में पारदर्शिता की मांग बढ़ रही है। यदि संसद नियमों में संशोधन करे, जैसे सुनवाई को लाइव प्रसारित करने का प्रावधान, तो यह संभव हो सकता है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक संस्कृति में, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष एक–दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ऐसी सुनवाई से घोटाला ही फूट सकता है, जैसे संसद में अवरोध या मीडिया ट्रायल। फिर भी, लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह विचारणीय है।

किसी भी लोकतंत्र में, सत्ता में कोई भी पार्टी क्यों न हो, ऐसे अधिकारियों को बुलाने, उन्हे जवाबदेह बनाने के कई लाभ हैं। सबसे पहले, यह जवाबदेही सुनिश्चित करता है। चुने हुए प्रतिनिधि कार्यकारी अधिकारियों से सवाल कर सकते हैं, जो जनता की ओर से होता है। इससे भ्रष्टाचार, दुरुपयोग या नीतिगत असफलताओं पर रोशनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में पटेल की सुनवाई से एपस्टीन फाइलों पर जनता को जानकारी मिली, जो अन्यथा छिपी रह सकती थी। भारत में यदि ऐसा हो, तो सरकारी योजनाओं या जांचों की पारदर्शिता अवश्य बढ़ेगी।दूसरा, यह जांच और संतुलन की व्यवस्था को मजबूत करता है। लोकतंत्र में कोई भी शाखा निरंकुश नहीं होनी चाहिए। विधायिका द्वारा कार्यकारी को बुलाना सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। सत्ता में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, यह प्रक्रिया नीतियों को जनहित में रखती है। तीसरा, जनता की भागीदारी बढ़ती है। सार्वजनिक सुनवाई से लोग सूचित होते हैं, ।

गोला–बारूद में आत्म निर्भरता

समय और परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक चीज की अहमियत होती है। हमारे देश में कहा भी गया है–जहां काम आवे सुई, काह करै तलवारि। यह बात सेना पर भी लागू होती है। लड़ाई केवल टैंकों और मिसाइलों से ही नहीं जीती जा सकती है। कहीं–कहीं गोला–बारूद महत्वपूर्ण हो जाता है। हम 2026 के नये सूरज का जब इंतजार कर रहे थे। तभी यह खुश खबरी मिली कि हमारी सेना गोला–बारूद के मामले में लगभग आत्म निर्भर हो गयी है। भारतीय सेना अपनी जरूरत का 90 फीसद से अधिक गोला–बारूद देश के अंदर ही बना रही है। हमारी सेना को लगभग 200 अलग–अलग श्रेणियों के गोला–बारूद का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब तक हम रूस और इजरायल से इसका आयात करते थे। अब सिर्फ 10 प्रतिशत के लिए हमें दूसरे देशो की मदद लेनी पड़ेगी और उम्मीद यह है कि यह 10 फीसद गोला–बारूद भी शीघ्र ही मेड इन इंडिया हो जाएगा। देश के अंदर गोला–बारूद ही नहीं हैवी वेट टारबर्पीडो और सीक्यूवी कार्बाइन भी हमारी सेना और नौ सेना की ताकत को बढ़ाएंगी। इसके लिए वर्ष 2025 के अंतिम दिनों में 4666 करोड़ का डिफेंस करार सम्पन्न हुआ है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बीते साल सशस्त्र बलों के आध ुनिकीकरण के लिए 1 लाख 82 हजार 492 करोड़ के पूंजीगत अनुबंध ा भी किये जा चुके हैं।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध केवल अत्याधुनिक टैंकों या मिसाइलों से नहीं जीते जाते, बल्कि युद्ध क्षेत्र में गोला–बारूद की निर्बाध सप्लाई को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता से जीते जाते हैं। भारतीय सेना ने इसी 'सस्टेनेबिलिटी' को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया है। पहले भारत को महत्वपूर्ण गोला–बारूद और प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन (सटीक हमला करने वाले गोले) के लिए रूस, इजरायल या पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे संकट के समय आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना रहता था।

अब यह निर्भरता लगभग समाप्त हो गई है। बदलते वैश्विक भू–राजनीतिक समीकरणों और युद्ध के नए तौर–तरीकों को देखते हुए भारतीय सेना ने अपनी सामरिक तैयारियों में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव ने यह साबित कर दिया है कि अब युद्ध केवल कुछ दिनों का नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला 'लॉजिस्टिक्स गेम' बन गया है। इसी वास्तविकता को स्वीकारते हुए, भारतीय सेना ने गोला–बारूद की आपूर्ति में अभूतपूर्व आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सेना अब अपने शस्त्रागार के 90 प्रतिशत से अधिक गोला–बारूद का निर्माण देश के भीतर ही कर रही है।

भारतीय सेना वर्तमान में करीब 200 अलग–अलग श्रेणियों के गोला–बारूद और प्रिसिजन म्यूनिशन का इस्तेमाल करती है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 90 फीसदी अब 'मेक इन इंडिया' के तहत तैयार हो रहे हैं। शेष 10 फीसदी विशिष्ट श्रेणी के गोला–बारूद के लिए भी सेना, सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर तेजी से काम कर रही आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले तीन वर्षों में भारतीय रक्षा कंपनियों को लगभग 26,000 करोड़ रुपये के गोला–बारूद के ऑर्डर दिए गए हैं। इसके अलावा, सेना ने 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत करीब 16,000 करोड़ रुपये का एक नया 'ऑर्डर बास्केट' तैयार किया है, जो अगले कुछ वर्षों में घरेलू उद्योग को मिलेगा।

इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा भारतीय रक्षा निर्माण क्षेत्र को मिला है। खरीद प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है। अब स्थिति यह है कि कई महत्वपूर्ण गोला–बारूद श्रेणियों के लिए सेना के पास एक नहीं, बल्कि एक से अधिक घरेलू सप्लायर मौजूद हैं। यह प्रतिस्पर्धा न केवल कीमतों को नियंत्रित कर रही है, बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार ला रही है।

सिर्फ निर्माण ही नहीं, बल्कि सेना अब पूरी सप्लाई चेन को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। इसमें गोला–बारूद बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पुरानी फैक्ट्रियों का आध ुनिकीकरण और उत्पादन की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी शामिल है।

पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय ने 4,666 करोड़ के दो बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। ये समझौते सेना और नौसेना की युद्ध क्षमता को और मजबूत करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हुए। पहला कॉन्ट्रैक्ट 'क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन' के लिए है। इसके तहत सेना और नौसेना के लिए 4.25 लाख से ज्यादा ब्फ्ठ कार्बाइन खरीदी जाएंगी। ये आधुनिक और हल्की कार्बाइन तंग जगहों में लड़ाई के लिए बेहद कारगर होंगी। इससे 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा।

दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 'हेवीवेट टॉरपीडो' के लिए है। लगभग 1,896 करोड़ के रुपये इस सौदे के तहत नौसेना के 48 टॉरपीडो खरीदे जाएंगे। इन टॉरपीडो की आपूर्ति अप्रैल 2028 से शुरू होकर 2030 की शुरुआत तक पूरी होगी। इससे नौसेना की पनडुब्बियों की मारक क्षमता और आधुनिक तकनीकी ताकत बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2025–26 में अब तक सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1,82,492 करोड़ रुपए के पूंजीगत अनुबंध किए जा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्रालय ने सेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए 79,000 करोड़ रुपये मूल्य के लंबी दूरी के रॉकेट, मिसाइल, रडार सिस्टम और अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी प्रदान की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। बयान में कहा गया कि लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से भेदने के लिए पिनाका रॉकेट प्रणालियों की मारक क्षमता और सटीकता को बढ़ाने के वास्ते लंबी दूरी के दिशा निर्देशित रॉकेटों की खरीद की जा रही है। उन्नत रेंज वाली एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली (एमके–2) सामरिक युद्ध क्षेत्र तथा भीतरी इलाकों में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण संपत्तियों की रक्षा करेगी। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के लिए, उच्च आवृत्ति सॉफ्टवेयर रेडियो (एचएफ एसडीआर) मैनपैक की खरीद और उच्च ऊंचाई तथा लंबी दूरी वाली तथा दूर से संचालित विमान प्रणाली (आरपीएएस) को पट्टे पर लेने की मंजूरी भी दी गई है। (हिफी)

भगवान सूर्य को समर्पित है 2026

साल 2026 में सूर्य देव की मूर्ति या तस्वीर घर लेकर आएं और इसे पूर्व दिशा में रखें। घर में सूर्य देव की तस्वीर रखने से परिवार के सदस्यों की मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्हें अपने जीवन में खूब तरक्की मिलेगी।

वर्ष 2026 की शुरुआत शुभ संयोग के साथ हो रही है। 1 जनवरी को ही कई योग बन रहे हैं, जो ध ाार्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभकारी रहेगा। ऐसे में नए साल के दिन इन कार्यों को करने से पूरे साल सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वर्षा होगी। ज्योतिष शास्त्र में साल 2026 को अत्यंत ही महत्वपूर्ण वर्ष माना जा रहा है। अंक ज्योतिष के अनुसार, 2026 सूर्य का साल होगा। हर नया साल किसी न किसी ग्रह से संबंधित होता है। कौनसा साल किस ग्रह का होगा यह अंक योग के जरिए निकाला जाता है। जैसे साल 2026 का अंक योग निकाले तो 2. 0. 2. 6 = 10 फिर 1. 0 = 1। अंक ज्योतिष में अंक 1 के स्वामी सूर्य माने जाते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रह को मान–सम्मान, नेतृत्व, आत्मविश्वास, ऊर्जा और नई शुरुआत का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में साल 2026 में इन क्षेत्र में कई बड़े प्रभाव देखने के मिलेगा। मूलांक 1 वालों को साल 2026 में अपार सफलता, तरक्की और मान–सम्मान में वृद्धि मिलने के योग हैं।

साल 2026 में सूर्य देव की मूर्ति या तस्वीर घर लेकर आएं और इसे पूर्व दिशा में रखें। घर में सूर्य देव की तस्वीर रखने से परिवार के सदस्यों की मान–सम्मान में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्हें अपने जीवन में खूब तरक्की मिलेगी। तांबे का सूर्य चिन्ह भी लाना बहुत ही शुभ रहेगा। इस सूर्य चिन्ह को आप घर के मुख्य द्वार या पूर्व दिशा की दीवार पर लगा दें। प्रतिदिन इस पर गंगाजल छिड़कें और रोली का टीका लगाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और करियर में कामयाबी भी मिलेगी। अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो साल 2026 में तांबे की चीजें घर लेकर आएं। तांबे का लोटा, गिलास या तांबे की अन्य चीजें घर लाना शुभ होगा।

साल 2026 सूर्य का साल है। ऐसे में सूर्य देव की सात घोड़े वाले रथ पर सवार वाली तस्वीर घर लेकर आएं। इस तस्वीर को घर की पूर्व दिशा में लगाएं। सूर्य देव की यह तस्वीर ज्ञान और ऊर्जा के प्रतीक माना जाता है। घर में इस तस्वीर को रखने से ज्ञान में वृद्धि होती है। समाज में मान–सम्मान मिलता है और घर में सुख–समृद्धि बनी रहती है। अच्छा रहेगा रोजाना स्नान के बाद उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें।

तांबे के लोटे से ही सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल वाले लोटे में लाल फूल, रोली और अक्षत मिलाएं। रविवार के दिन गुड़, गेहूं, अन्न और धन का दान करें। जल चढ़ाते समय 'सूर्याय नमः' या 'घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें तथा पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इस साल नए साल की शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है। वहीं इस दिन साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। तो 1 जनवरी 2026 को गुरु प्रदोष है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नए साल के दिन रोहिणी नक्षत्र और रवि योग का संयोग भी बन रहा है। इसके अलावा 1 जनवरी को धनु राशि में सूर्य, बुध, मंगल और वैभव के कारक शुक्र मौजूद रहेंगे। इन सभी शुभ संयोग की वजह से ही नया साल बेहद खास और मंगलकारी रहेगा।

नए साल के पहले दिन गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र समेत अन्य जरूरी चीजों का दान करें। ऐसा करने से देवी–देवता प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आपके घर–परिवार पर सदैव बनी रहती है। इसके साथ ही देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना करें। संभव हो तो मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करें। पूजापाठ के साथ दिन की शुरुआत करने से पूरे वर्ष जीवन खुशहाल रहता है। जनवरी साल का पहला महीना होता है। जनवरी से ही नए साल की शुरुआत होती है। इस माह में कई बड़े व्रत–त्यौहार आते हैं जिनका हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। जनवरी में मकर संक्रांति से लेकर लोहड़ी और बसंत पंचमी जैसे बड़े त्यौहार आते हैं। इसके अलावा जनवरी में ही मौनी अमावस्या भी मनाई जाएगी। जनवरी में ही माघ महीने का आरंभ भी होता है। हिंदू धर्म में माघ माह का विशेष महत्व होता है। माघ में स्नान–दान, पूजा–पाठ और उपवास करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। महीने में प्रमुख व्रत देखें तो– 1 जनवरी, गुरुवार प्रदोष व्रत, 3 जनवरी 2026, शनिवार पौष पूर्णिमा, 6 जनवरी 2026, मंगलवार, सकट चौथ, 14 जनवरी 2026, बुधवार, मकर संक्रांति, पोंगल, 14 जनवरी 2026, बुधवार षटतिला एकादशी , 16 जनवरी, शुक्रवार, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, 18 जनवरी 2026, रविवार, मौनी अमावस्या, 23 जनवरी 2026, शुक्रवार, बसंत पंचमी, 25 जनवरी 2026, रविवार, रथ सप्तमी, 26 जनवरी, 2026, सोमवार भीष्म अष्टमी, 29 जनवरी, 2026, रविवार,

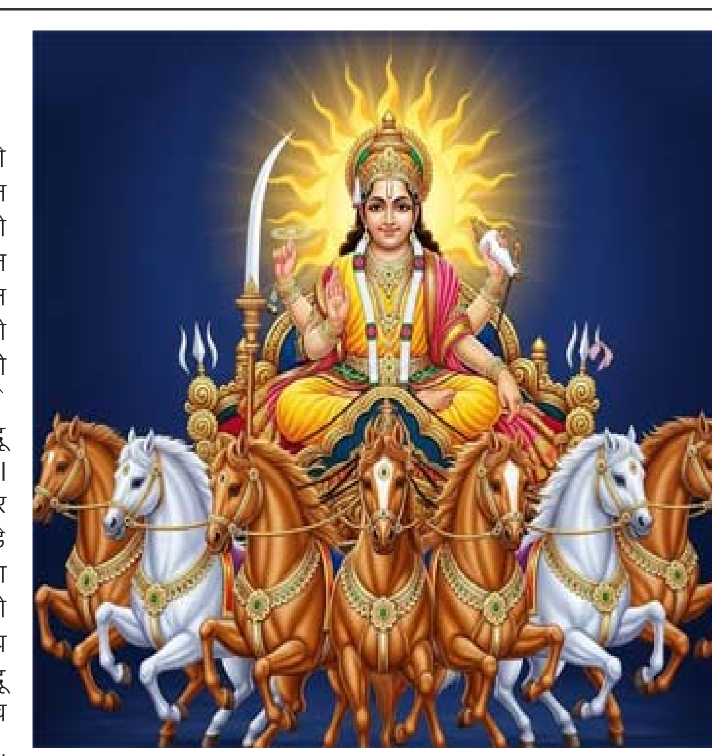

जया एकादशी और 30 जनवरी, शुक्रवार प्रदोष व्रत होगा। मौनी अमावस्या को माघ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान–दान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इस दिन व्रत और दान–पुण्य करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के सारे काम बिना बाधा के पूरे होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का भी विधान है। साल 2026 में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रयागराज में हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। इस दौरान मौनी के दिन संगम में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह दिन माता सरस्वती को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी की आराधना करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी माता सरस्वती के आशीर्वाद से अपार सफलता मिलती है। इस बार 23 जनवरी को बसंत पंचमी मनायी जाएगी। (हिफी)

शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी विश्वविद्यालय के विकास के समान भागीदार: कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल

लखनऊ(संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने 2 जनवरी को विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों एवं विभागों से जुड़े गैर–शिक्षण अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. अश्विनी कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रो. विक्रम सिंह यादव, वित्त अधिकारी डॉ. अजय कुमार मोहंती तथा पुस्तकालय अध्यक्ष डॉ. सुनील गोरिया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय से जुड़ी गैर–शैक्षणिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक सेवाओं की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की गई।संवाद के दौरान भविष्य की संभावनाओं, उभरती चुनौतियों और प्रशासनिक तंत्र को अधिक सुदृढ़, प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के उपायों पर सार्थक विचार–विमर्श हुआ। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के समग्र विकास को नई दिशा देना और कार्यसंस्कृति को और अधिक परिणामोन्मुख बनाना रहा।अपने संबोधन में कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों की समान भागीदारी और समन्वय से ही संस्थान सुचारु रूप से आगे बढ़ता है। उन्होंने विशेष रूप से नॉन–टीचिंग कर्मचारियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक सेवाओं के बिना शैक्षणिक गुणवत्ता की कल्पना संभव नहीं है। सभी को एक साझा रोडमैप को समझते हुए मिल–जुलकर कार्य करना चाहिए, ताकि गुणवत्ता–आधारित शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।प्रो. मित्तल ने कहा कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य ऐसे युवाओं का निर्माण करना है जो नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए समाज को दिशा दे सकें। सशक्त नेतृत्व वाले संस्थानों के परिणाम और प्रतिष्ठा दोनों ही उत्कृष्ट होते हैं। उन्होंने कौशल–आधारित और मूल्य–आधारित शिक्षा को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं का समाधान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निहित है। एक उच्च शिक्षण संस्थान होने के नाते यह शिक्षण एवं विशेष रूप से गैर–शिक्षण कर्मचारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के अनुरूप शिक्षा के माध्यम से एक प्रगतिशील, समावेशी और समान विकास वाला समाज तैयार किया जाए।कुलपति ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय स्वयं को आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है, ताकि विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके और शैक्षणिक वातावरण को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया जा सके।कार्यक्रम के दौरान कुलसचिव डॉ. अश्विनी कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रो. विक्रम सिंह यादव, वित्त अधिकारी डॉ. अजय कुमार मोहंती और पुस्तकालय अध्यक्ष डॉ. सुनील गोरिया ने भी नॉन–टीचिंग कर्मचारियों की भूमिका, उनकी कार्यकुशलता, समर्पण और विश्वविद्यालय की प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि गैर–शिक्षण स्टाफ की दक्षता और प्रतिबद्धता के बिना संस्थान का सुचारु संचालन संभव नहीं है।इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों और विभागों से जुड़े बड़ी संख्या में गैर–शिक्षण अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। संवाद कार्यक्रम को विश्वविद्यालय में सहभागिता, पारदर्शिता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

महिला किसान सशक्तिकरण को बड़ी मजबूती, एमकेएसवाई योजना के तहत 9.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति

लखनऊ(संवाददाता)। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के ग्राम्य विकास विभाग ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसवाई) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बड़ी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल 9 करोड़ 99 लाख 60 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह धनराशि एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत जारी की गई है।शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत एसएनए स्पर्श मॉड्यूल में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदर सैंक्शन के सापेक्ष अनुदान संख्या–83 (अनुसूचित जाति मद) के मानक मद–27 सब्सिडी के अंतर्गत केन्द्रांश के रूप में 5 करोड़ 99 लाख 76 हजार रुपये तथा राज्यांश के रूप में 3 करोड़ 99 लाख 84 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल 9 करोड़ 99 लाख 60 हजार रुपये की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किए जाने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्गत कर दिया गया है।उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा–निर्देशों एवं गाइडलाइन के अनुरूप समय से किया जाए। उन्होंने कहा है कि धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी और योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक हर हाल में समय पर पहुंचना चाहिए।जारी शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

आहरण एवं व्यय की प्रक्रिया योजना से संबंधित दिशा–निर्देशों तथा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएगी। स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, उनके परीक्षण और सत्यापन की जिम्मेदारी आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की होगी।इसके साथ ही स्वीकृत धनराशि के नियम संगत व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दायित्व भी आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपा गया है।

शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धनराशि के आहरण और व्यय के दौरान मितव्ययिता से संबंधित वित्तीय नियमों एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जामहिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत दी गई यह वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कृषि आधारित आजीविका को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भरता बढ़ाने और सामाजिक–आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

इंडियन रेडक्रास सोसाइटी की पहल से सरकारी अस्पतालों को मिला संबल, उ0प्र0 मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वितरित किए स्ट्रेचर, व्हीलचेयर व चिकित्सा उपकरण

लखनऊ(संवाददाता)। आज दिनांक 02 जनवरी, 2026 (शुक्रवार) को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय (सिविल), लखनऊ में स्ट्रेचर, व्हीलचेयर एवं चिकित्सा उपकरण वितरण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, शाखा लखनऊ द्वारा किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।कार्यक्रम के दौरान इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, लखनऊ के चेयरमैन ओ.पी. पाठक एवं सचिव अमरनाथ मिश्र द्वारा मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति–चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि रामानन्द कटियार, सचिव इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश तथा डॉ. जी.पी. गुप्ता, अपर निदेशक चिकित्सा, लखनऊ मण्डल को भी पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति–चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में निदेशक सिविल अस्पताल डॉ. कजली गुप्ता, निदेशक बलरामपुर अस्पताल डॉ. कविता आर्या, निदेशक लोकबंधु अस्पताल डॉ. संगीता गुप्ता, सीएमएस बलरामपुर अस्पताल डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी तथा सीएमएस सिविल अस्पताल डॉ. देवेश पाण्डेय को पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया।मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा 30 स्ट्रेचर, 30 व्हीलचेयर एवं 1000 पल्स ऑक्सीमीटर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी "सिविल" अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल एवं लोकबंधु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय को समान रूप से प्रदान किए गए। इस चिकित्सा सामग्री का उपयोग आवश्यकता के अनुसार जरूरतमंद रोगियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा, जिससे सरकारी अस्पतालों में उपचार व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।कार्यक्रम के अवसर पर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी को स्ट्रेचर एवं व्हीलचेयर प्रदान करने वाले दानदाताओं नवीन गुप्ता, अमित अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, दीपक अग्रवाल एवं रजत कुमार गुप्ता को प्रशस्ति–पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाजसेवा में व्यापारियों की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया गया।अपने उद्बोधन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि व्यापारी वर्ग सदैव समाज सेवा और दान कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है, इसी कारण उन्हें भामाशाह स्वरूप दानवीर की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा निरंतर किए जा रहे मानवीय सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था की जनहितकारी गतिविधियाँ अत्यंत प्रशंसनीय और अनुकरणीय हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी इसी प्रतिबद्धता के साथ सेवा कार्यों को आगे बढ़ाती रहेगी।इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, लखनऊ के चेयरमैन ओ.पी. पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के निर्धन, असहाय, वृद्ध एवं दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना एक महान सेवा कार्य है, जिससे मानवीय मूल्यों को मजबूती मिलती है। वहीं सचिव अमरनाथ मिश्र ने कहा कि ऐसे सेवा कार्यक्रम समाज में सहयोग, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने समाज के सक्षम व्यक्तियों और संस्थाओं से आगे आकर ऐसे मानवीय कार्यों में सहयोग देने की अपील भी की।कार्यक्रम में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, लखनऊ के चेयरमैन ओ.पी. पाठक, सचिव अमरनाथ मिश्र, कोषाध्यक्ष नवीन गुप्ता सहित जितेन्द्र सिंह चौहान, माजिद अली, नफीस, रूपकुमार शर्मा, आलोक कुमार सक्सेना, सिद्धार्थ गुप्ता समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

इंदौर में प्रदूषित पानी से मौतें सरकारी लापरवाही का भयावह उदाहरण, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी

लखनऊ (संवाददाता)मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रदूषित पानी पीने से अनेक निर्दोष नागरिकों की मौत और कई अन्य लोगों के गंभीर रूप से बीमार हो जाने की अति–दुखद और चौंकाने वाली खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना केवल एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी तंत्र की लापरवाही, उदासीनता और जवाबदेही की कमी को उजागर करने वाली गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई है। स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश और चिंता स्वाभाविक रूप से देखने को मिल रही है।साफ पानी और स्वच्छ हवा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना किसी भी सरकार की पहली और अनिवार्य जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यही नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य की आधारशिला होती हैं। इसके बावजूद इंदौर जैसी घटना का सामने आना यह दर्शाता है कि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की तरह ही बुनियादी जनसुविधाओं के क्षेत्र में भी सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार किस हद तक घातक रूप ले चुका है। इस लापरवाही की कीमत आम नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है और कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ जा रहे हैं, जो अत्यंत दुखद और चिंताजनक है।यह घटना स्पष्ट संकेत देती है कि जल आपूर्ति, शुद्धिकरण व्यवस्था और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े तंत्र में गंभीर खामियां मौजूद हैं। यदि समय रहते निगरानी, गुणवत्ता परीक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती, तो ऐसी दर्दनाक स्थिति से बचा जा सकता था। नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करने वाली इस तरह की शर्मनाक घटनाओं को किसी भी स्थिति में सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राज्य सरकार को तत्काल और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी सरकारी तंत्र अपनी जिम्मेदारियों से बच न सके। साथ ही जल आपूर्ति व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर उसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना जरूरी है।इसके साथ ही केंद्र सरकार को भी इस गंभीर प्रकरण का संज्ञान लेकर प्रभावी हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि देश के किसी अन्य राज्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाएं दोहराई न जा सकें। यह केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश की नागरिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। समय रहते ठोस कार्रवाई ही आम जनता के विश्वास को बहाल कर सकती है और भविष्य में ऐसे जानलेवा हादसों को रोक सकती है।

डुमरियागंज में जनसेवा के साथ मनाया गया सांसद जगदंबिका पाल का जन्मदिवस, चार हजार जरूरतमंद परिवारों को बांटे गए कंबल

सिद्धार्थनगर(संवाददाता)। लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल के जन्मदिवस के अवसर पर तुलसियापुर में आयोजित जन्मदिवस अभिनंदन समारोह जनसेवा और सामाजिक सरोकार का प्रतीक बनकर सामने आया। कार्यक्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने सहभागिता की और इस अवसर पर लगभग चार हजार गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को कंबल वितरित किए गए। मंत्री ए. के. शर्मा ने स्वयं कई जरूरतमंद परिवारों को कंबल प्रदान कर सेवा और संवेदना का संदेश दिया।समारोह को संबोधित करते हुए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने सांसद जगदंबिका पाल को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे ऐसे जननेता हैं जो पूरी तरह जनता के प्रति समर्पित हैं और जिनकी बात दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गंभीरता से सुनी जाती है। उन्होंने कहा कि सांसद पाल की राजनीति का केंद्र सदैव क्षेत्र का विकास और आमजन का कल्याण रहा है। यही कारण है कि डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर आज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।मंत्री ए. के. शर्मा ने बताया कि नगर विकास विभाग द्वारा सिद्धार्थनगर जनपद में लगभग दो हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य कराए गए हैं, जिनमें से आधे से अधिक कार्य सांसद जगदंबिका पाल की अनुशंसा पर स्वीकृत हुए और पूर्ण कराए गए। उन्होंने कहा कि विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी सांसद के सतत प्रयासों से अनेक मजरों और गांवों तक बिजली पहुंची है, जिससे ग्रामीण जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। मंत्री ने कहा कि नए वर्ष और जन्मदिवस जैसे अवसरों पर विदेश या पर्यटन स्थलों पर न जाकर जनता के बीच रहकर उत्सव मनाना उनके जनसेवक होने का प्रमाण है।इस अवसर पर सांसद जगदंबिका पाल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आज तेजी से उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति बन रहा है। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली थी, उस समय भारत विश्व की ग्यारहवीं अर्थव्यवस्था था, जबकि आज भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजनीति को कभी सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं माना, बल्कि इसे जिम्मेदारी, सेवा और कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया है।सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि जनता का विश्वास और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और इसी विश्वास के बल पर वे निरंतर क्षेत्र के विकास और गरीब, कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनसेवा ही उनका संकल्प और उद्देश्य है।

कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष साधना चौहान, चेयरमैन गोविंद माधव, जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। कंबल वितरण कार्यक्रम को क्षेत्र में सर्द मौसम के बीच जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा गया और इसे सामाजिकसंवेदनशीलता का सशक्त उदाहरण माना गया।

माघ मेला में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर का उद्घाटन, नेताजी की मूर्ति न लगाने पर प्रशासन की कड़ी आलोचना

प्रयागराज(संवाददाता)। को माघ मेला परिसर में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान द्वारा आयोजित सेवा शिविर का उद्घाटन नेता विरोधी दल विधानसभा माता प्रसाद पांडेय द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। शिविर का उद्देश्य माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराना और श्रद्धेय नेताजी के समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाना रहा।शिविर संचालन कर रहे संस्था अध्यक्ष एवं इलाहाबाद शहर उत्तरी से पूर्व प्रत्याशी संदीप यादव ने बताया कि इससे पूर्व कुंभ मेला के दौरान श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित की गई थी, किंतु माघ मेले में प्रशासन द्वारा मूर्ति स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मूर्ति स्थापना से जुड़े प्रयासों के चलते प्रशासन ने उनके विरुद्ध फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए, जो पूरी तरह अनुचित और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं।उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में माता प्रसाद पांडेय ने श्रद्धेय नेताजी के जीवन से जुड़े अनेक संस्मरण साझा करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव का पूरा जीवन संघर्ष, समाजवाद और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने संदीप यादव के खिलाफ की गई प्रशासनिक कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है।समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने भी प्रशासन के निर्णय को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय नेताजी केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक हैं और उनकी मूर्ति न लगाने का फैसला समाजवादी विचारधारा का अपमान है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर शिविर उद्घाटन के उपरांत राधा और भगवान कृष्ण की मूर्तियों की विधिवत पूजा कर माघ मेला स्थल पर शिविर का शुभारंभ किया गया।कार्यक्रम में विधायक हाकिम लाल बिंद, विधायक विजमा यादव, विधायक गीता पासी, विधान परिषद सदस्य मान सिंह यादव, संदीप पटेल तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव लल्लन राय की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता और श्रद्धालु भी शिविर उद्घाटन के साक्षी बने।

समाजवादी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के विचार और संघर्ष किसी प्रशासनिक रोक से सीमित नहीं किए जा सकते और समाजवादी आंदोलन उनके सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ता रहेगा।

मिशन शक्ति5.0 के तहत बीकेटी में छात्राओं-छात्रों को किया गया जागरूक, महिला सुरक्षा और साइबर सतर्कता पर दिया गया विशेष संदेश

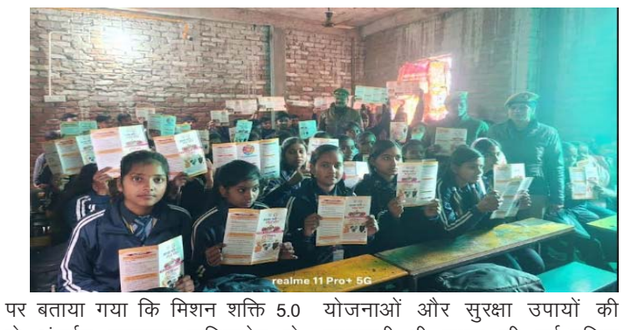

लखनऊ(संवाददाता)। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को थाना बीकेटी क्षेत्र के आदर्श इंटर कॉलेज, एयर फोर्स रोड, बक्शी तालाब में महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। "मिलकर हाथ बढ़ाएँ, मिशन शक्ति को सफल बनाएँ" के संदेश के साथ आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं, छात्रों और महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति सजग बनाना रहा।दिनांक 02 जनवरी 2026 को आयोजित इस जागरूकता सत्र में थाना बीकेटी पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 एवं एंटी रोमियो अभियान के अंतर्गत "गुड टच" और "बैड टच" की जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, नारी स्वावलंबन, घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनी प्रावधानों, साइबर अपराधों से बचाव और डिजिटल माध्यमों पर सतर्कता जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। छात्राओं और छात्रों को यह बताया गया कि किसी भी संदिग्ध या आपात स्थिति में वे बिना भय के पुलिस और संबंधित हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।कार्यक्रम के दौरान यूपी कॉप ऐप, सीईआईआर पोर्टल और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने 112, 1090, 181, 1076, 101, 108 और साइबर हेल्पलाइन 1930 जैसे महत्वपूर्ण नंबरों की उपयोगिता समझाते हुए बताया कि इनका समय पर प्रयोग जीवन और सम्मान दोनों की रक्षा कर सकता है। साथ ही साइबर फ्रॉड, ओटीपी साझा न करने, अनजान लिंक पर क्लिक न करने, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान सावधानी बरतने और तथाकथित "डिजिटल अरेस्ट" जैसी भ्रांतियों से दूर रहने के लिए भी बच्चों को जागरूक किया गया।इस अवसर पर बताया गया कि मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत लखनऊ कमिश्नरेट के सभी 54 थानों पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जहां महिला निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक और महिला उपनिरीक्षक की तैनाती की गई है। इन केंद्रों का उद्देश्य थानों पर आने वाली महिलाओं की समस्याओं का त्वरित, संवेदनशील और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना है। मिशन शक्ति केंद्र के लिए जारी विशेष सीयूजी नंबर की जानकारी भी विद्यार्थियों को दी गई, ताकि वे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर सीधे संपर्क कर सकें।कार्यक्रम में उपनिरीक्षक सुरेश चंद्र राजपूत, महिला आरक्षी रचना शर्मा और महिला आरक्षी रेशम रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यालय में उपस्थित लगभग 50 से 60 छात्र–छात्राओं और अध्यापिकाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया और जागरूकता संदेश को गंभीरता से सुना। पंपलेट वितरित कर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं और सुरक्षा उपायों की जानकारी भी साझा की गई।पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मिशन शक्ति 5.0 केवल एक अभियान नहीं, बल्कि महिलाओं और बालिकाओं में आत्मविश्वास, सुरक्षा और सम्मान की भावना विकसित करने की सतत प्रक्रिया है। यह पहल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराती है और एक सुरक्षित, समान एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में मजबूत नींव रखती है। ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को न केवल कानून की जानकारी दी जा रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सजग नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।कार्यक्रम को महिला सुरक्षा, सम्मान और साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम माना जा रहा है, जिसे आगे भी निरंतर जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

संपूर्ण समाधान दिवस में गृहकरएजलकर की 76 आपत्तियों पर हुई सुनवाई, कई मामलों में मिली राहत

लखनऊ(संवाददाता)। शहरवासियों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से नगर निगम लखनऊ द्वारा शुक्रवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को आयोजित होने वाली इस व्यवस्था के तहत नगर निगम मुख्यालय, लालबाग स्थित त्रिलोकनाथ सभागार में प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक समाधान दिवस संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर सुषमा खर्कवाल ने की।संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान नगर निगम के विभिन्न जोनों से गृहकर एवं जलकर से संबंधित कुल 76 आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। इनमें 60 आपत्तियाँ गृहकर तथा 16 जलकर से जुड़ी रहीं। जोनवार स्थिति की बात करें तो जोन–1 से 25, जोन–2 से 5, जोन–3 से 5, जोन–4 से 1, जोन–6 से 11, जोन–7 से 11 तथा जोन–8 से 2 आपत्तियाँ दर्ज की गईं, जबकि जोन–5 से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।ळै सर्वेक्षण के बाद कर निर्धारण से संबंधित आपत्तियों पर मौके पर ही सुनवाई की गई और कई मामलों में नागरिकों को तत्काल राहत दी गई। जानकीपुरम सेक्टर–एफ निवासी अनिल कुमार गोबिल का ळै के अनुसार निर्धारित वार्षिक मूल्य 44,280 रुपये था, जिसे निस्तारण के उपरांत घटाकर 21,262 रुपये कर दिया गया। इसी प्रकार हुसैनाबाद निवासी गजन्फर नवाब के मामले में वार्षिक मूल्य 14,625 रुपये से घटाकर 11,025 रुपये निर्धारित किया गया।पीर बुखारा क्षेत्र निवासी मोहम्मद हारून रिजवी का वार्षिक मूल्य 36,000 रुपये से घटाकर 21,600 रुपये किया गया। वहीं वृंदावन सेक्टर–8 निवासी राहुल सिंह रावत के मामले में ळै के अनुसार 24,206 रुपये के स्थान पर 17,496 रुपये वार्षिक मूल्य तय किया गया। विकास नगर सेक्टर–6 निवासी मीरा गुप्ता के प्रकरण में 19,926 रुपये से घटाकर 7,128 रुपये वार्षिक मूल्य निर्धारित किया गया। समाधान दिवस के दौरान नागरिकों द्वारा सफाई व्यवस्था, सड़कों व गलियों की मरम्मत, सीवर लाइन, ड्रेनेज व्यवस्था, मार्ग प्रकाश और कूड़ा उठान से संबंधित शिकायतें भी दर्ज कराई गईं। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने इन समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए कई मामलों में मौके पर ही आवश्यक निर्देश जारी किए।

कार्यक्रम में नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह, जोनल अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, पार्षदगण तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस नगर निगम और शहरवासियों के बीच संवाद का सशक्त माध्यम है। नगर निगम का प्रयास है कि नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण पारदर्शी, न्यायसंगत और समयबद्ध ढंग से किया जाए। गृहकर एवं जलकर से संबंधित आपत्तियों का मौके पर समाधान कर आम नागरिकों को राहत देना प्राथमिकता है। उन्होंने शहरवासियों से इस मंच का अधिक से अधिक लाभ उठाने और स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित लखनऊ के निर्माण में सहयोग करने की अपील की।नगर निगम ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया कि वे भविष्य में संपूर्ण समाधान दिवस में अपनी शिकायतों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय से उपस्थित होकर इस सुविधा का लाभ उठाएँ।

नववर्ष के उपलक्ष्य मे हैदराबाद थानाध्यक्ष की अगुवाई मे रोपे गये पौधे

शाम को चाय व पकौडी की दावत के साथ मनाया गया नववर्ष

गोला गोकर्णनाथ खीरी। नववर्ष के उपलक्ष्य मे यानि की ऐक जनवरी दो हजार छब्बीस की अल सुवह हैदराबाद थाना परिसर मे थानाध्यक्ष सुनील कुमार मलिक की अगुवाई मे समस्त थाना स्टाफ ने थाना मे हरे भरे फलदाई व औषधीय पौधों का रोपण कर हरियाली का संदेश दिया है।

इस दौरान हैदराबाद थानाध्यक्ष सुनील मलिक ने बताया कि हमारे चारो चरफ प्रदूषण आये दिन बढ रहा है गर्मियो मे पारा 40 सेल्सियस के पार हो जाता है। इस लिये हम सब की जुमामेदारी है ,ऐक वृक्ष अपनी मां के नाम, जे जूडकर ऐक वृक्ष हमेशा आपने जीवन काल मे लगाये व ऊसकी सुरक्षा भी करे।

इसके साथ ही हैदराबाद थानाध्यक्ष ने नव वर्ष के आगमन के चलते सभी पत्रकार साथियो के साथ मिलकर गरामा गरम चाय के साथ पकौडियो का निस्ता भी कराया गया। इस अवसर पर एस एस आई संत पाल सिंह राठौर उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, हेमंत कटियार, विनोद मिश्र,खेमेन्द्र सिह,सहित तमाम पुलिस व महिला आरक्षी मौजूद रही।

लोहिया संस्थान में शुरू हुई तीसरी कैथ लैब, हृदय रोगियों को मिलेगा तेजी से इलाज

लखनऊ। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोगियों के उपचार का इंतजार अब कम होगा। रोगियों को समय पर जांच और उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई नई कैथ लैब अत्यंत उपयोगी साबित होगी। इससे इमरजेंसी हृदय रोगियों की जांच और उपचार लैब में ही तुरंत संभव हो सकेगा। बातें उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को लोहिया संस्थान में तीसरी कैथ लैब के उद्घाटन के अवसर पर कहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार हो रहा है। अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है तथा आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान आधुनिक उपचार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रहा है। कम समय में संस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यहां रोबोटिक सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट और न्यूरो साइंस सेंटर के माध्यम से अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग में दो कैथ लैब कार्यरत थीं। तीसरी कैथ लैब के शुरू होने से जांच और उपचार की क्षमता और बढ़ेगी। अभी प्रतिदिन लगभग 20 एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर से संबंधित प्रक्रियाएं की जा रही हैं, जो अब बढ़कर लगभग 30 प्रतिदिन हो जाएंगी। इससे गंभीर हृदय रोगियों को शीघ्र, सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिल सकेगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्डियोलॉजी सेवाओं पर बढ़ता भरोसा आंकड़ों से स्पष्ट है। प्रतिदिन 250 से 300 मरीज कार्डियोलॉजी ओपीडी में परामर्श के लिए आ रहे हैं। वार्षिक रूप से लगभग 50 हजार ओपीडी परामर्श और करीब 8 हजार मरीजों को कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती किया जाता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एक और नई कैथ लैब की खरीद प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके बाद संस्थान में कुल चार कैथ लैब होंगी। साथ ही इस वर्ष कार्डियोलॉजी विभाग को अत्याधुनिक तकनीकों से पूरी तरह सुसज्जित किया जा रहा है, जिसमें एडवांस्ड इकोकार्डियोग्राफी मशीन, दो पोर्टेबल इको मशीनें, टीएमटी (ट्रेडमिल टेस्ट) सुविधा और आईवस जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल हैं।

कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉ. सीएम सिंह, सीएमएस डॉ. विक्रम सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अरविंद सिंह, मातृ शिशु रेफरल हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. श्रीकेश सिंह, कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. भुवन चंद्र तिवारी, रजिस्ट्रार डॉ. सुब्रत चंद्रा सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहे।

रोगियों से लिया फीडबैक

कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग रूम का निरीक्षण किया और उपचाररत रोगियों से बातचीत की। उन्होंने परिजनों से भी उपचार की जानकारी ली और इलाज के दौरान आने वाली समस्याओं पर फीडबैक प्राप्त किया।

सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में उत्तर प्रदेश बनेगा थीम स्टेट, लोक कला और ओडीओपी उत्पादों की दिखेगी वैश्विक झलक

लखनऊ। भारतीय लोक परंपराओं और शिल्प कला के वैश्विक उत्सव

सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का 39वां संस्करण 31 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक हरियाणा में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आयोजन में वर्ष 2026 के लिए उत्तर प्रदेश को थीम स्टेट के रूप में चयनित किया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस अवसर पर प्रदेश की प्राचीन सभ्यता, समृद्ध लोक कलाओं, विशिष्ट हस्तशिल्प एवं हथकरघा परंपराओं, लोक नृत्य–संगीत और स्थानीय व्यंजनों के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करेगा। साथ ही कारीगरों की सृजनशीलता और शिल्प कौशल को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने बताया कि सूरजकुंड मेला 2026 कई मायनों में विशेष होगा। एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत राज्य की हस्तशिल्प एवं हथकरघा परंपराओं को सशक्त मंच प्रदान करने के लिए 40 विशेष हस्तशिल्प स्टॉल स्थापित किए जाएंगे। इनमें फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां, कन्नौज का इत्र, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, वाराणसी, लखनऊ और भदोही की जरी–जरदोजी एवं चिकनकारी सहित विभिन्न जिलों के विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मेले में संस्कृति, खानपान और पर्यटक सुविधाओं का दायरा पहले से कहीं अधिक व्यापक रखा गया है।

उन्होंने आगे बताया कि मेले के दौरान प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पांच से छह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, लोक संगीत और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जिनमें प्रतिदिन लगभग 50 से 100 कलाकार सहभागिता करेंगे। इसके अतिरिक्त, मेले के तीन विशेष अवसरों (सप्ताहांत) पर उत्तर प्रदेश की पारंपरिक और समकालीन वेशभूषा, आभूषण एवं फैशन को प्रदर्शित करने वाले फैशन शो भी आयोजित किए जाएंगे, जो आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे।

उत्तर प्रदेश के स्टॉलों के साथ–साथ पूरे मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक वातावरण सृजित किया जाएगा। पाथवे पर मूंज बुनाई, धान की बालियां, खुर्जा पॉटरी और ब्लैक पॉटरी से प्रेरित डिजाइन उकेरे जाएंगे। प्रत्येक जिले और शिल्प के लिए विशेष साइनेज और क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से आगंतुक शिल्प निर्माण प्रक्रिया, कारीगरों की प्रोफाइल, जिले की विशिष्ट पहचान और सतत विकास से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह प्रत्येक जिला अपनी कला के माध्यम से सांस्कृतिक दूत की भूमिका निभाएगा।

प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति, श्री अमृत अभिजात ने कहा कि सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 उत्तर प्रदेश के लिए अपनी समृद्ध लोक परंपराओं, हस्तशिल्प विरासत और सांस्कृतिक विविधता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। थीम स्टेट के रूप में राज्य के विभिन्न जिलों के ओडीओपी आधारित हस्तशिल्प स्टॉल कारीगरों की सृजनशीलता को जीवंत रूप में सामने लाएंगे। ईको–फ्रेंडली साज–सज्जा, डिजिटल तकनीक और क्षेत्रीय व्यंजनों के माध्यम से यह आयोजन वोकल फॉर लोकल और सतत पर्यटन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा।

फरीदपुर से भाजपा विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक से निधन, सर्किट हाउस में बैठक के बाद बिगड़ी तबीयत

बरेली। फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को आकस्मिक निधन हो गया। सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ बैठक में शामिल होने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल पीलीभीत रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। शुक्रवार को सर्किट हाउस में विभिन्न सरकारी योजनाओं और कानून–व्यवस्था को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में फरीदपुर विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल भी मौजूद थे। बैठक समाप्त होने के बाद जैसे ही वह कक्ष से बाहर निकले, अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें पीलीभीत बाईपास स्थित मेडिसिटी हॉस्पिटल (हायर सेंटर) पहुंचाया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, भर्ती किए जाने तक उनकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। डॉ. श्याम बिहारी लाल फरीदपुर से दूसरी बार विधायक थे। इसके साथ ही वह महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर भी कार्यरत थे। उनके निधन की खबर मिलते ही बरेली, फरीदपुर और लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिस–प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे।

सृष्टि में तीन की संख्या महत्वपूर्ण

(सुनील शर्मा)

लखीमपुर खीरी। इस सृष्टि में तीन की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन देवता मुख्य हैं। तीन देवियां हैं। तीन लोक हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती तीन नदियां मुख्य हैं। परब्रह्म की तीन विशेषताएं प्रसिद्ध हैं,सत, चित, आनन्द। उसकी प्राप्ति के लिए ऋषियों ने तीन सूत्र बताए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। त्रेता युग में तीन असुर थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। द्वापर के तीन असुर कंस, जरासंध और शिशुपाल। कलयुग के तीन राक्षस हैं अज्ञान, अभाव, अनीति। तीनों ने समाज को घेर रखा है, चारों तरफ इनका साम्राज्य है। त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान शंकर का त्रिशूल उठा था।उसी प्रकार इन राक्षसों को मारने के लिए ज्ञान, कर्म तथा भक्ति की गंगा बहानी पड़ेगी उक्त विचार हैं श्री वेदमाता गायत्री प्रचार समिति के संस्थापक अध्यक्ष पं राजेश दीक्षित के जिन्होंने ग्राम कैमासुर सिद्ध बाबा स्थान पर पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ की महापूर्णाहुति कराते हुए कहे। महायज्ञ में संगीत एवं प्रज्ञा गीत प्रस्तुत किया विष्णु कुमार शर्मा व अमित जी ने। महायज्ञ की महापूर्णाहुति में सैकड़ों महिला, पुरुष परिजनों ने राष्ट्र कल्याण हेतु आहुतियां देकर पूण्य को प्राप्त किया। महायज्ञ में समस्त ग्राम वासियों ने सहयोग किया।

सड़क हादसा पीड़ितों को निजी अस्पतालों में मिलेगा निशुल्क इलाज, आईएमए संग सीएमओ ने की अहम बैठक

लखीमपुर खीरी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी चिकित्सालयों को व्यवस्था से जोड़ने के लिए सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सड़क हादसों में घायल मरीजों को दी जाने वाली शासकीय सुविधाओं और योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की गई। सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता ने बताया कि यदि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति 24 घंटे के भीतर किसी निजी चिकित्सालय में भर्ती होता है, तो उसे एक सप्ताह तक अधिकतम 1. 5 लाख रुपये तक का इलाज निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस उपचार की पूरी धनराशि शासन द्वारा निजी चिकित्सालय को दी जाएगी, जिससे मरीज और उसके परिजनों पर आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राहवीर योजना के तहत ऐसे नागरिकों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा जो किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को एंबुलेंस या अन्य माध्यम से चिकित्सालय पहुंचाते हैं। ऐसे मददगार राहवीरों को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए संबंधित चिकित्सालय को राहगीर (चिकित्सालय पहुंचाने वाले व्यक्ति) की जानकारी सुरक्षित रखनी होगी। दोनों योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क हादसे देश और प्रदेश के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में हर वर्ष लगभग 1.6 लाख से अधिक लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है, जबकि करीब 4.5 लाख से अधिक लोग घायल होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी प्रतिवर्ष 20 हजार से अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की जाती हैं, जिनमें हजारों लोगों को गंभीर चोटें आती हैं। ऐसे में निजी अस्पतालों की भागीदारी से घायलों को समय पर इलाज मिल सकेगा और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने में मदद मिलेगी। बैठक में एसीएमओ डॉ. एसपी मिश्रा, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ डॉ. धनीराम, डिप्टी सीएमओ डॉ. प्रमोद वर्मा, डिप्टी सीएमओ डॉ. अमितेश द्विवेदी सहित आईएमए अध्यक्ष डॉ. अखिलेश खरे, डॉ. अखिलेश वर्मा और डॉ. मनोज शर्मा उपस्थित रहे।

टीम ने बर्बरता पूर्वक परिजनों को पीटा घरेलू सामान भी तोड़ा

निघासन खीरी। थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव रामनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिविल कपड़ों में पीएसी ट्रक से उतर कर लोगों ने घर में तोड़फोड़ कर परिजनों को पीटा व तीन लड़कियों को साथ में ले गए मामला बीते गुरुवार को गांव राम नगर में मुखबिर की सूचना पर थाना सुजौली से आई टीम ने अवैध कच्ची शराब बना रहे शराब माफियाओं को पकड़ने की फिराक से टीम ने जाल बिछाया लेकिन सुगबुगाहट लगने पर अवैध कच्ची शराब माफिया वहां से भाग निकले इसी दौरान खेत में काम कर रहे किसान माला सिंह रामप्रवेश समेत अन्य किसानों को शक के आधार पर पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन किसान अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागे निकले।

ग्रामीणों ने लगाया आरोप

थाना सुजौली टीम द्वारा अवैध कच्ची शराब की छापेमारी की गई थी इसी क्रम में टीम ने शक के आधार पर किसानों को उनके घर तक दौड़ा कर पकड़ा लेकिन पूछताछ न करने की बजाय उनसे मारपीट करने लगे साथ ही महिला व पुरुष जो भी मिला जमकर मारा गया इसी दौरान एक महिला का सर भी फूटा जबकि टीम ने घरेलू सामान (कुर्सी,वाशिंग मशीन और गैस चूल्हा) मिट्टी के चूल्हे व एक बाइक को भी तोड़ा इतना ही नहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हम लोगों को बद्दी बद्दी गलियां व डंडों से भी मारा गया है किसान कुलदीप ने आरोप लगाया है कि सिविल ड्रेस में जो भी थे मेरे घर का लॉक तोड़ा और घर के अंदर तोड़फोड़ करने के साथ–साथ घर का चूल्हा और गन्ने का रखा हुआ पैसा 69597 भी नहीं मिले ये पुलिस वाले थे या डकैत जो इस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया हम लोगों को बहुत मारा पीटा है।

पुलिस ने बताया घटना चक्र

थाना प्रभारी सुजौली से जब इस बबात पर जब पूछा गया तो बताया कि टीम अवैध कच्ची शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए गई थी लेकिन टीम पर हमला किया गया जिससे तनावपूर्ण की स्थिति पैदा हो गई लेकिन जब टीम द्वारा घर में घरेलू सामान व मारपीट के बारे में पूछा गया तो थाना प्रभारी बातों को गोल–माल करते नजर आये।

फैमिली आईडी से शत-प्रतिशत डीबीटी लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश, योजनाओं के एकीकृत डाटाबेस पर जोर

लखनऊ। मुख्य सचिव श्री एस. पी. गोयल ने फैमिली आईडी दृ एक परिवार एक पहचान योजना से संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं के शत–प्रतिशत लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से फैमिली आईडी से आच्छादित किया जाए। मुख्य सचिव ने फैमिली आईडी डाटाबेस के इंटीग्रेशन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि सभी विभाग अपनी–अपनी योजनाओं एवं सेवाओं को इस डाटाबेस से लिंक करें और निर्धारित अंतराल पर डाटा साझा करना सुनिश्चित करें। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि भारत सरकार की योजनाओं से आच्छादित प्रदेश के लाभार्थियों का डाटा प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों से समन्वय स्थापित करें। प्राप्त डाटा को फैमिली आईडी डाटाबेस से इंटीग्रेट किया जाए। साथ ही फैमिली आईडी डाटाबेस के आधार पर विभिन्न योजनाओं के लिए संभावित लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं से जोड़ा जाए। बैठक में प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग द्वारा फैमिली आईडी योजना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें विभागवार फैमिली आईडी लिंकेज की प्रगति की जानकारी दी गई और इस योजना के माध्यम से परिवार के पात्र सभी सदस्यों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के महत्व को रेखांकित किया गया। इस अवसर पर फैमिली ई–पासबुक का भी प्रदर्शन किया गया। ई–पासबुक के माध्यम से आमजन अपने परिवार अथवा परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो रही सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी आसानी से देख सकेंगे। इसके साथ ही फैमिली आईडी डाटाबेस के आधार पर वे उन योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे, जिनके लिए वे पात्र हैं।

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत 9.99 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसवाई) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल 9 करोड़ 99 लाख 60 हजार रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

यह धनराशि अनुदान संख्या–83 (अनुसूचित जाति मद) के अंतर्गत एसएनए स्पर्श प्रणाली पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदर सैंक्शन के सापेक्ष राज्यांश के रूप में अनुमन्य की गई है। परियोजना के तहत केंद्रांश की धनराशि 5 करोड़ 99 लाख 76 हजार रुपये तथा राज्यांश की धनराशि 3 करोड़ 99 लाख 84 हजार रुपये है। इस प्रकार कुल स्वीकृत राशि 9,99,60,000 रुपये (नौ करोड़ निन्यानबे लाख साठ हजार मात्र) है। स्वीकृत धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखी जाएगी तथा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय की जाएगी। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं गाइडलाइंस के अनुरूप समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। जारी शासनादेश के अनुसार धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकता के अनुसार चरणबद्ध किया जाएगा। धनराशि के आहरण एवं व्यय में योजना संबंधी दिशा–निर्देशों, मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों तथा वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

नववर्ष के उपलक्ष्य मे ग्लोबल इंटर कॉलेज मे सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन।

गोला गोकर्णनाथ खीरी ।नव वर्ष के अवसर पर ग्लोबल इंटर कॉलेज में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमो के समापन समारोह पर नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की पूर्व पालिका अध्यक्ष ने समापन कार्यक्रम का शुभारम्भ मां सरस्वती के चित्र पर पूजन करके फीता काट कर किया। विशिष्ट अतिथि आलोक तिवारी शैलेन्द्र सक्सेना अशोक कनौजिया सिम्पी चौधरी अनुज खरे संदीप प्रजापति राजेश वर्मा अरुण शर्मा उपस्थित रहे। पूर्व पालिका अध्यक्ष मीनाक्षीअग्रवाल नेअपने संबोधन में कहा किनववर्ष के अवसर पर विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम अत्यन्त सराहनीय है और उन्होंने विद्यालय परिवारके प्रति आभार व्यक्त किया। और पालिका अध्यक्ष ने आयोजित बाल मेलाका अवलोकन किया और विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमके प्रस्तुती करण की प्रशंसा कीऔर पूर्व पालिका अध्यक्ष ने छात्र–छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विद्यालय के प्रबंधक अवधेश वर्मा ने मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया औरमुख्य अतिथिसहितसभी अतिधियों का कार्यकर्म में सहभागिता करने के लिएआभार प्रकट किया कार्यक्रम का सफल संचालन महेंद्र वर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मनोज वर्मा सहित शिक्षक शिक्षिकाएं एवं भारी संख्या में छात्र–छात्राएं सहित गणमान्य बन्धु उपस्थित रहे।

फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम के तहत नगर में किया गया प्रसाद वितरण

लखीमपुर खीरी।नववर्ष के अवसर पर इस्कॉन लखीमपुर खीरी द्वारा शहर में भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर संकीर्तन से हुई, जिसमें सैंकड़ो श्रद्धालुओं ने भजन–कीर्तन के साथ शहर में आध्यात्मिक वातावरण बना दिया।इस्कॉन लखीमपुर के संचालक सुनील

मुकुंद प्रभु ने बताया कि दिन में फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम के तहत नगर में प्रसाद वितरण किया गया और इस्कॉन मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में 101 किलो फूलों से भगवान का अभिषेक किया गया, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ ही मटकी फोड़ प्रतियोगिता, बाल प्रतियोगिताएं एवं फूलों की होली में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। शहर में विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण कर इस्कॉन लखीमपुर खीरी द्वारा सेवा भाव का संदेश दिया गया। नववर्ष के इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया।समस्त जानकारी मीडिया प्रभारी नूतन मिश्रा एवं सह मीडिया प्रभारी स्पर्श सिन्हा ने दी।

पुरानी बिल्डिंग तोड़ते समय हुआ हादसा

लखीमपुर खीरी। जिले के जंग बहादुरगंज के केन ग्रोवर्स इंटर कॉलेज में पुरानी जर्जर बिल्डिंग को तोड़ते समय हादसा हो गया जिसमें 3 मजदूर घायल हो गए। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार हादसे में विक्कू पुत्र सर्वेश सिंह ,भल्लू पुत्र लाला सिंह ,रंजीत पुत्र ईश्वरी हुए घायल समस्त निवासी रामपुर नानकारी थाना रौजा जनपद शाहजहांपुर के थे घायलों को एंबुलेंस द्वारा ब्ब पसगवां ले जाया गया जहां साथ में केन ग्रोवर्स इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक हरिश्चंद्र वर्मा जी भी साथ में गए अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की छुट्टी कर दी गई है।

इंटर कॉलेज की पीछे साइड में बनी बिल्डिंग जिसे जर्जर घोषित कर दिया गया था उसे नीलामी द्वारा प्रक्रिया पूरी करके ठेकेदार के द्वारा तुड़वाया जा रहा था और कई कमरों की छत टूट चुकी थी कुछ कमरे बाकी रह गए थे जिसे मजदूरों द्वारा तोड़ा जा रहा था इसी बीच आज सुबह यह घटना घट गई घटना में जो भी तीन मजदूर घायल हुए थे उन्हें एंबुलेंस द्वारा ब्ब पसगवां ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की छुट्टी कर दी गई

एचएसएनएस उपकर अधिनियम 2026: पान मसाला व तंबाकू निर्माताओं के लिए पंजीकरण, भुगतान और मशीन बंदी के नियम जारी

लखनऊ। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा (एचएसएनएस) उपकर अधिनियम, 2026 के तहत पान मसाला और तंबाकू उत्पाद निर्माताओं के लिए पंजीकरण, उपकर भुगतान और मशीन बंद करने पर छूट (एबेटमेंट) से जुड़े स्पष्ट नियम जारी कर दिए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय (च्ठ) ने 2 जनवरी 2026 को जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) में मौजूदा और नए सभी निर्माताओं को 1 फरवरी 2026 से पोर्टल पर FORM HSNS REG–01 के माध्यम से पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति के लिए ACES पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। यदि किसी निर्माता की मशीनें एक से अधिक कारखानों में स्थापित हैं, तो प्रत्येक कारखाने के लिए अलग–अलग पंजीकरण कराना होगा। मौजूदा पान मसाला और तंबाकू उत्पाद निर्माताओं को 1 फरवरी 2026 से ही आवेदन करना आवश्यक है, क्योंकि उपकर भुगतान की जिम्मेदारी भी उसी तिथि से प्रभावी होगी। आवेदन करने के सात कार्य दिवस के भीतर पंजीकरण स्वतः स्वीकृत माना जाएगा और FORM HSNS REG–02 के माध्यम से पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। उपकर की गणना वास्तविक उत्पादन के आधार पर नहीं, बल्कि मशीनों की संख्या और उनकी अधिकतम पैकिंग गति के आधार पर की जाएगी, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची प्प् की तालिका–1 में निर्धारित है। उपकर का भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख तक करना होगा, जबकि संबंधित माह का रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक FORM HSNS RET–01 में दाखिल करना अनिवार्य होगा। यदि कोई निर्माता नई मशीन जोड़ता है, तो उसे 15 दिनों के भीतर थ्व्ड भ्ैछ क्म्ब्–01 के माध्यम से नई घोषणा देनी होगी। वहीं, किसी मशीन के लगातार 15 दिनों से अधिक बंद रहने की स्थिति में प्रो–राटा आधार पर उपकर में छूट (एबेटमेंट) का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मशीन बंद करने से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व संबंधित अधिकारी को सूचना देकर मशीन को सील कराना आवश्यक होगा।

नियमों के तहत फैक्ट्री परिसर में सभी मशीनों को कवर करने वाला सीसीटीवी सिस्टम अनिवार्य किया गया है, ।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, ४० वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी २/३७६ रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ० प्र० से प्रकाशित।

सम्पादक

आरती पाण्डेय

ek-

9807059191- 9026560178

Email-

adbhutsamachar@gmail.com

adbhutsamachar@hotmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।